Title: Need for early implementation of National Education Policy.

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, देश में गरीबी, कुपोषण से लेकर अन्य सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का स्तर किसी भी देश के विकास का मापदंड माना जाता है। शायद इसी वजह से हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमान अवसरों को खत्म करने की है। इसी वजह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क रखने का लक्षय रखा था किंतु अफसोस है कि आजादी के ५० साल बाद भी लक्षय प्राप्त नहीं हो सका है और विश्व के सबसे अधिक ४ करोड़ २४ लाख अशिक्षित भारत में हैं। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण स्कूलों के संचालन और प्रबन्धन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का न होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रौढ़ शिक्षा की दर १८ प्रतिशत थी जो १९९१ में ५२ प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार १९५१ में महिला साक्षरता केवल ९ प्रतिशत थी जो १९९२ में ४३ प्रतिशत हो गई, किंतु मुझे इन आंकड़ों में भी वास्तविकता नजर नहीं आती, क्योंकि तीन में से एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले ही छोड़ देता है और दो में से एक बच्चे को स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। ग्रामीण इलाके में एक सर्वे के अनुसार पांचवी कक्षा का एक भी छात्र दूसरे दर्जे का हिन्दी और हिसाब में सफल साबित नहीं हुआ। तमिलनाडू में किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में चौथी कक्षा के केवल आधे शिक्षक ही चौथी कक्षा के हिसाब के पर्चे के ८० प्रतिशत सही उत्तर दे पाए। ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की बात दिवःस्वपन सी प्रतीत होती है।

अतः मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अविलम्ब लागू करें ताकि देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके।